न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 73/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि.) रजि. कार्यालय 19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह महलाना पुत्र रघुवीर सिंह

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **रामप्रसाद पुत्र टीकुराम** निवासी ग्राम चैलासी, तहसील व जिला सीकर, 332041
2. **विकास पुत्र रामप्रसाद** निवासी ग्राम चैलासी, तहसील व जिला सीकर, 332041
3. **कमला पत्नी रामप्रसाद** निवासी ग्राम चैलासी, तहसील व जिला सीकर, 332041

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

आदेश

दिनांकः 04 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मनोज कुमार वर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 3 क्रमशः **रामप्रसाद पुत्र टीकुराम, विकास पुत्र रामप्रसाद** एवं **कमला पत्नी रामप्रसाद** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की अचल सम्पति **आवासीय भूखण्ड जो कि भूमि खसरा नम्बर 78/547, ग्राम चैलासी, पटवार हल्का श्यामपुरा, तहसील व जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 288.48 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में मदन व डालुराम की भूमि, पश्चिम दिशा में डुंगाराम मेघवाल की भूमि, उत्तर

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

दिशा में सुखदेवाराम मेघवाल की भूमि एवं दक्षिण दिशा में रास्ता व सोलाराम स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹8,50,000/— (अक्षरे रूपये आठ लाख पचास हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **17.07.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **17.07.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 3 क्रमशः **रामप्रसाद पुत्र टीकुराम, विकास पुत्र रामप्रसाद** एवं **कमला पत्नी रामप्रसाद** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की अचल सम्पति **आवासीय भूखण्ड जो कि भूमि खसरा नम्बर 78/547, ग्राम चैलासी, पटवार हल्का**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

श्यामपुरा, तहसील व जिला सीकर (राज.) में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 288.48 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– मदन व डालुराम की भूमि, पश्चिम दिशा में डुंगाराम मेघवाल की भूमि, उत्तर दिशा में सुखदेवाराम मेघवाल की भूमि एवं दक्षिण दिशा में रास्ता व सोलाराम स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **04 मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर